RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –III GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - **POLITICAL**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. राजकोषीय संघवाद से क्या आशय हैं ?

उत्तरः–राजकोषीय संघवाद का आशय केन्द्र व राज्यों में वित्तीय शक्तियों के उचित आवंटन से हैं। राज्यों के आर्थिक विकास हेतु केन्द्र सभी आवश्यक प्रयास करेंगा व राज्य भी वित्तीय अनुशासन व केन्द्र को सहयोग देगा।

2. जिला नियोजन समिति के गठन का क्या उद्देश्य हैं ?

उत्तरः– जिला नियोजन समिति का उद्देश्य जिले के पंचायत व नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संगठित करना व संपूर्ण जिले के लिए समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करना हैं।

3. पंचायती राज संबंधी निर्वाचन हेतु राजस्थान में तय की गई न्युनतम शैक्षणिक योग्यता क्या हैं ?

उत्तरः–संरपच पद हेतु आठवी पास (जनजातीय क्षेत्र में पाँचवी पास) व पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य हेतु दसवीं पास होने की शैक्षणिक अर्हता तय की गई हैं।

4. अशोक मेहता समिति किससे संबंधित हैं ?

उत्तरः–पंचायती राज से संबंधित जिसमें द्विस्तरीय पंचायती राज, SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राजनैतिक दलों द्वारा पंचायतीराज चुनाव में भाग लेने व पंचायत राज संस्थानों को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने जैसे सुझाव दिये गये ।

5. PESA एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या हैं ?

- ☞ जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन व प्रशासनिक प्रदान करना।
- ☞ जनजातियों की परम्परा व संस्कृति का संरक्षण
- ☞ ऐसे क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का केन्द्र ग्राम सभा को बनाना।

6. भारतीय प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व हैं ?

उत्तरः–स्थानीय स्वशासन शासन के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा हैं। इसमें ग्रामीण व नगरीय सत्ता को राजनैतिक अधिकार एवं उत्तरदाायित्व दिये जाते हैं। यह जनता के अंतिम स्तर तक शासन की सुविधाओं को पहुचाने के लिए आवश्यक है, इसके साथ यह उच्च स्तरीय शासन पर सत्ता एवं उत्तरदायित्व के भार को कम करता हैं। निम्न स्तर तक जनता की समस्याओं की पहचान करने व सरकार की योजना के प्रचार एवं अनुपालन में स्थानीय स्वशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। भारत की ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में स्थानीय स्वशासन की प्रासंगकिता में वृद्धि हो जाती हैं।

7. सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशे लिखिए ?

उत्तरः–सरकारिया आयोग (1983) ने स्पष्ट किया कि केन्द्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में ढ़ाँचागत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं केवल कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन के सुझाव दिये-

i. राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से जाये एव राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना किसी ठोस कारण बाधित न किया जायें।

ii. अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग न हो, यह अंतिम विकल्प हो।

iii. अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन किया जायें।

iv. अखिल भारतीय सेवाओं को सशकत बनाया जायें।

8. "भारत में केन्द्र व राज्यों में प्रशासनिक विवाद सैदव विद्यमान रहे हैं।" कथन की व्याख्या करे एवं समाधान के लिए किये गे प्रयासों का उल्लेख कीजिए ?

उत्तरः–भारत संघ जो राज्यों के संघ के रूप में हैं, यहाँ संघ व राज्यों के मध्य विभिन्न प्रशासनिक विषय विवादास्पद हैं। अनुच्छेद 256 व 257 के तहत राज्यों द्वारा कार्यपालिका शक्ति के उपयोग संबंधी प्रावधान किये गये हैं किन्तु भारत की राजनैतिक व प्रशासनिक संरचना में विवाद ग्रस्त प्रशासनिक आधार विद्यमान है। राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही हैं व केन्द्र द्वारा राज्यों में विरोधी दल की सरकार होने पर कार्य संचालन में बाधा व अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग के आरोप लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवकों के आचरण व उनकी केन्द्र के लिए अधिक प्रतिबद्धता एवं राज्यों की अनुपति के बिना अर्द्धसैन्य बलों की तैनाती CBI की जाँच राज्य केन्द्र में मतभेद के प्रमुख आधार हैं। केन्द्र–राज्य संबंधों की समीक्षा पर विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए इनमें राज्य पुनर्गठन आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारिया आयोग, पुछी आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवदेन प्रमुख हैं। इस संदर्भ में अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका में वृद्धि (नीति आयोग GST परिषद) जैसे प्रयास किये जा रहे हैं।

सारथि एकेडमी